भास्कर एक्सक्लूसिव • प्रदेश के करोड़ों नागरिकों का डेटा तैयार हो रहा, योजना के हिसाब से लाभार्थी की पहचान करेगा 'स्मार्ट' प्लेटफॉर्म

किन योजनाओं के पात्र हैं आप, AI बताएगा, प्रक्रिया खुद पूरी करेगा, सीधे लाभ मिलेगा

मुकेश माथुर | जयपुर

लोकसभा चुनाव में कितने ही नैरेटिव चल रहे हों लेकिन लाभार्थी योजनाएं हमेशा पार्टियों के केन्द्र में रहेंगी। हर घोषणापत्र लुभावनी योजनाओं से अटा है। इस बीच राजस्थान सरकार पहली ऐसी सरकार बनने जा रही है, जो योजनाओं को हर लाभार्थी तक तेजी से ले जाने के लिए एआई का बड़े पैमाने पर उपयोग करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) करीब 100 विभागों की अनुमानित 250 से ज्यादा योजनाओं को अपने नए प्लेटफॉर्म- 'स्मार्ट' पर लाने जा रहा है। 'स्मार्ट' प्रदेश के करोड़ों नागरिकों की पात्रता खुद जान कर मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजेगा कि वे किस-किस योजना के लिए पात्र हैं। योजना का लाभ व्यक्ति तक पहुंचाने का सारा काम भी सॉफ्टवेयर ही करेगा। लाभार्थी को किसी भी योजना के लिए एप्लिकेशन तक नहीं लगानी पड़ेगी। लाभार्थी सिर्फ स्वीकृति देगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, पेंशन, छात्रवृत्ति से जुड़ी हर सेवा सीधे मिलने लगेगी।

अजमेर निवासी आमना (47) व पुष्कर की अमरी देवी (67) को 1150 रु. एकल नारी पेंशन मिल रही है। 75 साल की होंगी तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। बढ़ा हुआ पैसा सीधे मिलने लगेगा। क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग 'स्मार्ट' प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसकी कुछ योजनाओं को इस सॉफ्टवेयर पर ले लिया गया है।

केजरीवाल की डोर स्टेप डिलीवरी से एक कदम आगे

एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार योजनाओं को घर तक ले जाने का दावा कर रही है, वहीं राजस्थान सरकार अलग तरह के मिशन में जुटी है

जहां सरकारी तंत्र आगे बढ़ कर खुद लाभार्थी की पहचान कर योजना का लाभ पहुंचाएगा। स्मार्ट का पूरा नाम है सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम। पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी और अब क्रियान्वयन शुरू हुआ है। 17 विभागों की 79 योजनाओं को इससे जोड़ा जा चुका है। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त विभाग की योजनाओं का ऑटोमेशन किया जा रहा है और अगले छह माह में काफी योजनाओं का लाभ इससे मिलना शुरू हो जाएगा। जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने से शुरू कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति सहित सभी तरह की नागरिक सेवाएं और लाभार्थी योजनाओं की सहज उपलब्धता इसके जरिए हो सकेगी।

डेटा सरकार के पास है, एआई उसे योजनाओं से जोड़ेगा

डीओआईटी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह के अनुसार जन आधार कार्ड के जरिए डेटा उपलब्ध है। एआई हर व्यक्ति की अर्हताओं को वर्गीकृत करेगा, लगातार अपडेट करेगा और कौन किस योजना के मापदंड पूरे करता है इसकी जानकारी एकत्र करेगा। सिंह के अनुसार सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक ले जाने का देश में इस स्तर का पहला काम है जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसी कंपनियां भी पहल कर हमसे जुड़ी हैं। कई राज्यों की सरकारें भी योजना की जानकारी ले रही हैं।

मोदीजी का लक्ष्य है लोगों की जिंदगी आसान हो : राठौड़

हमारे पास डेटा है और राज्य की सभी योजनाएं आईटी से ट्रेक हो ही रही हैं। एआई का उपयोग करते हुए तकनीक और गवर्नेंस को आपस में जोड़ कर योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश है- स्मार्ट। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। प्रधानमंत्री मोदीजी का लक्ष्य भी रहता है कि आम आदमी की जिंदगी किस तरह आसान की जाए। उसी दिशा में यह प्रयास है।

-राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री